उत्तर प्रदेश का पंचायती राज :

सत्ता की लूट के नये भागीदार गांव तक

अब ठेके पर पढ़ायेंगे "शिक्षा मित्र" और "आचार्य" और सरकारीकर्मी बनेंगे ठेकाकर्मी

मुकुल श्रीवास्तव

आजकल उत्तर प्रदेश के सरकारी हलकों से लेकर समाचार पत्रों तक में एक बात की बड़ी धूम मची है। राजधानी लखनऊ से लेकर गांवों-कस्बों तक में बड़ी-बड़ी होर्डिंगें लगायी जा रही हैं; अखबारों में लगातार इश्तेहार छप रहे हैं; सूचना विभाग द्वारा भारी पैमाने पर साहित्य वितरित किया जा रहा है। मसला भी संगीन है--सत्ता के विकेन्द्रीकरण उर्फ "जनतांत्रीकरण" का। शासन की बागडोर सीधे पंचायतों को यानी "जनता" के हाथों में सौंपने का दिवास्वप्न पूरा किया है कल्याण सरकार ने। मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार से प्रेरणा लेकर और पंचायतों को वहां से ज्यादा अधिकार सौंपकर कल्याण सिंह ने ग्राम पंचायतों को सर्वाधिकार सम्पन्न कर दिया है।

वाह, क्या खूब ! जनतंत्र का झीना नकाब भी उतारकर फेंक चुकी कल्याण सिंह की भाजपा सरकार द्वारा "जनतांत्रीकरण" के लिए इतना बड़ा कदम ! है न आश्चर्य !

लेकिन ऐसा ही हुआ है ! "पंचायती राज संशोधन विधेयक" पारित हो चुका है और बेसिक शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, समाज कल्याण, युवा कल्याण एवं खेलकूद, कृषि, गन्ना, ग्राम पंचायत, भूमि विकास एवं जल संसाधन जैसे बारह विभाग और उनसे जुड़े 9 लाख कर्मचारी अब ग्राम पंचायतों के मातहत होंगे। पेंशन और वजीफा बांटने का काम भी पंचायते ही करेंगी। इनके अवकाश से लेकर वेतन भुगतान और लघु दण्ड दिये जाने तक अधिकार सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को होगा। और लोक सभा के चुनाव से ऐन पहले प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा सत्ता के इस विकेन्द्रीकरण का [बगैर सरकारी मीडिया का "दुरुपयोग" किये] प्रचार जोर-शोर से जारी है। सरकार का दावा है कि इन कामों के गांवों में जाने से उसकी गुणवक्ता बढ़ जायेगी, देखभाल बेहतर होगी तथा खर्च कम हो जाएंगे।

आइए देखें, सरकार के इस दावे की, सत्ता के विकेन्द्रीकरण की असलियत!

सत्ता के विकेन्द्रीकरण के पहले चरण में जिन बारह विभागों को ग्राम पंचायतों को सौंपा गया है, वे सभी "मृत संवर्ग" घोषित कर दिये गये हैं। इनमें से लगभग साठ हजार कर्मचारी प्रतिवर्ष तरक्की पाएंगे अथवा अवकाश ग्रहण करेंगे। यह मृत काडर होगा, जिनकी जगह नयी नियुक्तियां नहीं होगी। इनकी जगह काम करने के लिए रु० 500/- से लेकर 2250/- तक माहवार देकर ठेके पर काम करवाया जाएगा। मतलब यह है कि 6000 रुपये महीना पाने वाले कर्मचारी का स्थान 500 रुपये पाने वाला व्यक्ति लेगा और वह भी स्थायी नहीं होगा–ठेके पर अल्पावधि के लिए रक्खा जाएगा। लम्बे संघर्षों के दौरान अर्जित पेंशन-बोनस-भत्ते का अधिकारी वह कदापि नहीं होगा, उसकी नौकरी की भी गारंटी नहीं होगी। इस प्रकार "कम खर्चे में कामों की गुणवत्ता" सुधारी जाएगी।

> दिगत आधी सदी के दौरान भारतीय गांवों में पूंजीवादी विकास के फलस्वरूप पैदा हुए कुलकों-फार्मरों-भूस्वामियों और गांवों के मवधनाढ्यों को पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लूट का हिस्सेदार बनाने का एक कारगर माध्यम है यह पंचायती राज।

प्राथमिक विद्यालयों की दशा और भी दयनीय होगी। यहां पढ़ाने की बागडोर संभालेंगे "शिक्षा मित्र" और "आचार्य"। इस वक्त बेसिक शिक्षा परिषद के 96 हजार स्कूलों और राज्य के सत्रह हजार मान्यता प्राप्त स्कूलों में 20 हजार शिक्षकों की तत्काल भर्ती किये जाने की जरूरत है। वह भी तब, जबकि प्राथमिक विद्यालयों में महज दो शिक्षक होंगे। इस वक्त बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में साढ़े तीन लाख से ज्यादा तथा जूनियर हाईस्कूल में 78 हजार शिक्षक कार्यरत हैं। इन शिक्षकों में से तीस हजार से ज्यादा हर साल अवकाश ग्रहण कर लेते हैं।

पंचायती राज के तहत, राज्य सरकार ने तय किया है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए अब पंचायतें ठेके पर शिक्षक नियुक्ति करेंगी। "शिक्षा मित्र" का दर्जा पाने वाले इन अध्यापकों के लिए इण्टरमीडिएट पास होना और स्थानीय होना जरूरी होगा। "कम खर्चे" पर "उत्तम गुणवक्ता" के लिए इन शिक्षकों को एक माह का प्रशिक्षण दिया जाएगा और दस माह के वेतन का अनुबंध किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान इन्हें 450 रु० मानदेय (वेतन नहीं) दिया जाएगा और 10 महीने तक प्रतिमाह रु० 2250/- दिया जाएगा। इन्हें ग्रीष्मावकाश का वेतन नहीं मिलेगा। इनके कामकाज से पंचायतें "संतुष्ट" होंगी तो अगले वर्ष पुनः इनसे अनुबंध किया जाएगा।

दूसरी योजना है 'शिक्षा गारंटी योजना'। इसके तहत छह से ग्यारह साल तक के कक्षा एक व दो में पढ़ने लायक 30 बच्चों के लिए खुलने वाले स्कूलों में पढ़ाने का काम करेंगे "आचार्य"। विश्व बैंक के सहयोग से पंचायतों द्वारा नियुक्त इन "आचार्यों" को रु० 1000/- प्रतिमाह दिया जाएगा।

दरअसल, आर्थिक संकटों के दुश्चक्र में फंसी राज्य सरकार को उबरने का एक बेहतरीन रास्ता यही नजर आया कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के नाम पर एक मुश्त 9 लाख शिक्षकों-कर्मचारियों का पद ही समाप्त कर दिया जाए और ठेके पर काम करवाकर वेतन के मद में खर्च हो रहे 16 हजार करोड़ रुपयों में से भारी हिस्सा बचा लिया जाए।

उल्लेखनीय है कि इस वक्त राज्य सरकार 28 हजार करोड़ रुपये का राजस्व व्यय कर रही है, और राजस्व आय है 22 हजार करोड़ रुपये। नौकरशाही से लेकर विधायकों-मंत्रियों के पूरे लवाजमात पर होने वाले "मेगा" खर्च, नयी आर्थिक नीति लागू करने और अन्य वित्तीय समायोजनों के कारण राज्य सरकार कर्ज के जिस मकड़जाले में उलझी है, उसे 12 हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष

कर्ज का व्याज चुकाने में खर्च हो जा रहा है। इन कर्जों के बावजूद इस वक्त राज्य सरकार के ऊपर 6 हजार करोड़ रुपये का राजस्व "घाटा" है। इन्हीं "घाटों" को पूरा करने का बेहतरीन नुस्खा है पंचायती राज।

> सत्ता के इस "विकेन्द्रीकरण" से इस व्यवस्था को एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि गांवों के माहौल में फूट और बिखराव की, झगड़ों-फौजदारियों और मुकदमेबाजियों की तल्खी कुछ और गहरी हो जायेगी। और जातीय-मज़हबी-क्षेत्रीय बंटवारे जितने अधिक होंगे व्यवस्था के संकट से उत्पन्न होने वाले विद्रोह को रोकने में उतने कारगर साबित होंगे।

यह तो पंचायती राज का एक पहलू है। दूसरा पहलू दूरगामी है—भूमण्डलीकरण के दौर में जारी आर्थिक नीतियों का एक हिस्सा है। विगत आधी सदी के दौरान भारतीय गांवों में पूंजीवादी विकास के फलस्वरूप पैदा हुए कुलकों-फार्मरों-भूस्वामियों और गांवों के नवधनाढ्यों को पूंजीवादी-साम्राज्यवादी लूट का हिस्सेदार बनाने का एक कारगर माध्यम है यह पंचायती राज।

आज गांवों की स्थिति काफी बदल गयी है। पिछले चार-पांच दशकों के दौरान हुए पूंजीवादी विकास से गांवों में एक नया सम्पत्तिशाली तबका पैदा हुआ है, फला-फूला है। इनमें कुछ पुराने भूस्वामी हैं जिन्होंने आधुनिक खेती के तौर तरीके अपनाकर अपने प्रभाव और समृद्धि को नये रूप में बरकार रक्खा है। कुछ जमींदारी के दौर के वे खुशहाल काश्तकार हैं जिन्होंने आजादी के बाद अपना आर्थिक आधार काफी मजबूत बना लिया है। इसके अलावा कोटा-परमिट, ठेका-पट्टी और नये-नये व्यवसाय का लाभ उठाकर एक नया सम्पत्तिशाली तबका भी पैदा हुआ है। गांवों के ये दौलतमन्द तबके पूंजीशाही के स्थानीय आधार-स्तम्भ हैं। इनकी संस्कृति पैसे की निर्मम संस्कृति है। वर्तमान दौर की पूंजीवादी निर्मम लूट का हिस्सा इन्हें भी चाहिए।

बड़ा पूंजीपति अपने मुनाफे में कटौती करके अपने इन ग्रामीण छुटभैय्यों को तो कुछ देने से रहा। वह तो खाद-बिजली-पानी की सब्सिडी में ही कटौती करना चाहता है। खेती के नये उपकरणों से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा निचोड़ना चाहता है। लेकिन आखिरकार वह उसका छोटाभाई है—उसे वह ज्यादा नाराज भी नहीं करना चाहता। सो, पंचायती राज ऐसा जरिया बनेगा जिसके माध्यम से पूंजीपतियों के मुनाफे में कटौती हुए बिना गांवों में पूंजी के इन स्तम्भों-कुलकों-फार्मरों-भूस्वामियों और नवधनाढ्यों को लूटने का, कमाने का अच्छा जरिया मिल जाएगा।

कहने की जरूरत नहीं कि पंचायती राज से पहले गांव का सम्पत्तिशाली वर्ग कैसे अपने आर्थिक हितों के लिए ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख, सहकारी समितियों के अध्यक्ष आदि पदों का सीधा इस्तेमाल करता रहा है। ग्राम सभा की जमीन और तालाबों के पट्टों का, सरकारी अनुदानों का, बैंक और ब्लाक की सब्सिडी का सीधा "उपयोग" किस तरह गांवों के "प्रभावशाली" व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अब पंचायती राज द्वारा इनके लूट के लिए निर्द्वंद रूप से बड़ा चारागाह मुहैय्या हो गया। इसमें नौकरशाही की एक हद तक पकड़ ढीली जरूर होगी, लेकिन मिलीभगत पूरी रहेगी।

सत्ता के इस "विकेन्द्रीकरण" से इस व्यवस्था का एक बड़ा लाभ यह भी होगा कि गांवों के माहौल में फूट और बिखराव की, झगड़ों-फौजदारियों और मुकदमेबाजियों की तल्खी कुछ और गहरी हो जायेगी। और जातीय-मज़हबी-क्षेत्रीय बंटवारे जितने अधिक होंगे व्यवस्था के संकट से उत्पन्न होने वाले विद्रोह को रोकने में उतने कारगर साबित होंगे।

और इन सबसे भाजपा पार्टीगत रूप से—अपने वोट की राजनीति के लिए भारी लाभ उठाने की फिराक में है। भाजपा का 'वोट बैंक' मुख्यतः सवर्ण हिन्दू जातियों में है, लेकिन गांव की मध्यम जातियों में कुछ खास नहीं है। कुलकों-नये भूस्वामियों में—गांवों की मध्यम जातियों के वोट बैंक में घुसपैठ के लिए पंचायती राज एक आधार का—एक बहाने का काम करेगा।

कुल मिलाकार प्रदेश का नया पंचायती राज जहां एक तरफ, ठेका पद्धति को, उजरती गुलामी को पैदा करेगा, गांव-गांव में शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगा, वहीं यह सत्ता की लूट की बंदरबांट का हिस्सा गांव के नये सम्पत्तिशाली तबके को बनायेगा। जहां एक ओर सरकार राजस्व घाटा पूरा करने के नाम पर प्राथमिक शिक्षा से ही मुकर जाएगी, वहीं साथ-ही-साथ भाजपा अपने जनाधार को गांवों में विस्तारित करने में कामयाब होगी।

यह है आज के दौर की एक भयावह साजिश। इसे समझना और इसके खिलाफ लम्बे संघर्ष की तैयारी में जुट जाना आज के दौर का एक जरूरी कार्यभार है। तभी हम इन नापाक इरादों को नेस्तनाबूद कर सकते हैं। •

राहुल फाउण्डेशन का गौरवशाली प्रकाशन

चीन की महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति के दौरान युवा कार्यकर्ताओं व आम लोगों की शिक्षा के लिए तैयार की गई मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र की विश्व-प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक

राजनीतिक अर्थशास्त्र के मूलभूत सिद्धान्त

दि शंघाई टेक्स्टबुक ऑफ पोलिटिकल इकॉनमी

खण्ड-एक (दूसरा खण्ड शीघ्र प्रकाश्य)

पृष्ठ : 208 मूल्य : 60 रुपये (पेपर बैक) 125 रुपये (सजिल्द)

बेर्तोल्त ब्रेष्त की जन्मशताब्दी

(10 फरवरी 1998-1999) के अवसर पर परिकल्पना की विशेष भेंट

बर्तोल्त ब्रेष्त : इकहत्तर कविताएं और तीस छोटी कहानियां

(ब्रेष्त के दुलर्भ चित्रों व कैरिकेचर्स से सज्जित)

मूल्य : 60 रुपये

अनुवाद (मूल जर्मन से) : **मोहन थपलियाल**

क्रान्तिकारी मजदूरों, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताओं, जनसंगठनकर्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी, विचारोत्तेजक व मार्गदर्शक पुस्तिका

कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन और उसका ढांचा

• लेनिन

बिगुल पुस्तिका-एक मूल्य-5 रुपये

"जुल्म के खिलाफ सिर्फ गुस्सा या सिर्फ बगावत ही काफी नहीं है। क्रान्ति एक सुनियोजित क्रिया है क्रान्ति में भाग लेने के लिए क्रान्ति के विज्ञान से परिचित होना जरूरी है।"

क्रान्ति का विज्ञान

• लेनी वुल्फ

मूल्य : 10 रुपये परिकल्पना प्रकाशन

इंक़लाब के लिए जरूरी है एक इंक़लाबी पार्टी और इंक़लाब पार्टी के लिए जरूरी है एक इंक़लाब अखबार

पढ़िए !

बिगुल

सम्पादकीय कार्यालय : 69, बाबा का पुरवा, निशातगंज, लखनऊ

मूल्य : तीन रुपये